इकाई 6

विकास का उदारवादी परिप्रेक्ष्य

इकाई की रूपरेखा

6.1 प्रस्तावना

6.2 विचारधारा के रूप में उदारवाद

6.3 उदारवादी विचारधारा की शाखाएँ

6.4 उदारवादी राज्य का क्रम-विकास

6.5 सामाजिक असमानता का समाधान

6.6 कल्याणकारी राज्य

6.7 नव-उदारवाद का उद्‌गम

6.8 उदारवादी संदर्भ की समालोचना

6.9 सारांश

6.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.1 प्रस्तावना

यूरोपीय ज्ञान से उत्पन्न उदारवाद का विकास 19वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ। वर्तमान समय में उदारवाद को आधुनिक राजनीति की सर्वाधिक प्रभावी विचारधाराओं में गिना जाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेन, फ्रांस और अंग्रेजी लेखकों ने नकारात्मक अर्थ में किया था।

सुधारवादी और प्रगतिवादी विचारधारा के रूप में इसका प्रयोग जनता के लिए किया गया। शीघ्र ही इसे अपने नकारात्मक अर्थ से मुक्ति मिल गई और यह एक आदर्शसूचक राजनीतिक शब्द बन गया। अब अधिकतर लोग स्वयं को ''उदार'' कहलाना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ है– ''मुक्त/स्वच्छंद विचारों वाला व्यक्ति'', ''सहृदय या उदार और सहनशील व्यक्ति'', ''लोगों के कल्याण के लिए अपने हितों का त्याग करना'', ''निष्पक्ष एवं तार्किक दृष्टि से प्रत्येक मुद्दे का समाधान करना'' और ''पूर्वाग्रह तथा अंधविश्वास'' को न मानने वाला व्यक्ति। इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी कानून और इस कानून को व्यवहार में अपनाने का विरोध करते हैं, जो किसी विशेष सामाजिक समूह को लाभों से वंचित रखता है। उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थक वाक् स्वतंत्रता, विरोध और धरना देने के अधिकार और महिलाओं, समलैंगिकों, कैदियों, शरणार्थियों के अधिकारों का समर्थन करते हैं।

इस इकाई में हमने उदारवादी परिप्रेक्ष्य से विकास की संकल्पना को समझने का प्रयास किया है। हम उदारवाद की मूल विचारधारा, व्यापार के ऊपर आर्थिक एवं राजनीतिक नियंत्रण के रूप में राज्य द्वारा शक्ति के साथ हस्तक्षेप और उदारवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका से शुरू करते हुए उदारवादी परिप्रेक्ष्य की समीक्षा और नव उदारवाद पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम उदारवादी परिप्रेक्ष्य से विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भूमिका या संरचना का निर्माण करते हुए अपना अध्ययन समाप्त करेंगे।

6.2 विचारधारा के रूप में उदारवाद

उदारवाद ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए एक विशेष परिप्रेक्ष्य प्रदान

ओर इशारा करता है जिसे हमेशा एक प्रक्रिया के रूप में पहचाना जाता है या जिसे एक ऐतिहासिक घटना या एक्नो-टेक्नो, मीडिया-फाइनेंस और आइडियो-स्केपस के बदलाव का परिणाम माना जाता है (अप्पादुरई 1996 : 32)। इसी आधार पर यह निरर्थक क्रिया आधुनिकीकरण को बदलता है क्योंकि आधुनिकतावादी और उनके प्रतिवादी 'सेंटर परिधि', 'उत्तर-दक्षिण', 'प्रथम विश्व—तृतीय विश्व', 'विकसित-विकासशील' आदि जैसे मॉडल द्वैतवादी विश्लेषण पर निर्भर थे।

आधुनिकीकरण की संकल्पना विश्व को अमेरिका और पश्चिमी यूरोपियाई सिद्धांतों और संस्कृति की छवि में पुन: निर्मित करने के विचार पर काफी संकीर्ण थी। असल में वैश्वीकरण पर चर्चाओं ने ऐसी प्रक्रिया को व्यक्त किया जिससे सांस्कृतिक एकता की सजातीय और एकरूपी प्रक्रियाओं को ध्यान में रख कर विश्व तेजी से एक-दूसरे के निकट और एकजुट हो रहा है। माइकल जैक्सन जैसी छवि या मैकडोनल्ड और नाइक के कार्पोरेट लोगों (स्वहव) वैश्विक जागरूकता के उदाहरण हैं।

5.8 सारांश

पारम्परिक (क्लासिकी) आधुनिकीकरण अध्ययनों और नव आधुनिकीकरण अध्ययनों के बीच की समानताओं को तीसरी दुनिया के विकास पर लक्षित स्थायी शोध में देखा जा सकता है।

पारम्परिक आधुनिकीरण नजरिए के अध्ययन और नव अध्ययनों के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे पारम्परिक (क्लासिकी) उपागम में परंपरा को विकास की अड़चन माना जाता है जबकि परंपरा के नये उपागम में इसे विकास का योज्य करक माना जाता है। पद्धति के हिसाब से क्लासिकी उपागाम, उच्च स्तर वाली अमूर्तता पर आधारित सैद्धांतिक रचना को लागू करती है, जबकि नया उपागम निश्चित ऐतिहासिक संदर्भ में ठोस केस अध्ययनों को लागू करती है। विकास की दिशा के संदर्भ में पारम्परिक (क्लासिकी) परिप्रेक्ष्य समरूपी पथ का प्रयोग करता है जो संयुक्त राज्यों और यूरोपियाई मॉडल के प्रति प्रवृत्त है। नया परिप्रेक्ष्य, विकास के बहुनिर्देशी पथ को तरजीह देता है। अंतत: पारम्परिक (क्लासिकी) परिप्रेक्ष्य बाहरी कारकों और द्वंद्व की उपेक्षा करता है यह नये उपागम से प्राप्त द्वंद्वों और बाहरी कारकों की ओर सजगता बरतने में तालमेल की सही छवि में नजर आता है। परिवर्तित संदर्भ में विकास एक चुनौती है और साथ ही आवास भी देता है।

इस इकाई की शुरुआत आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और आधुनिकीकरण सिद्धांत के विकास को समझने के प्रयास पर आधारित है। इकाई में चर्चा इस मुद्दे पर आगे चलती जाती है कि उत्तर-आधुनिकतावाद की सैद्धांतिक स्थिति किस प्रकार आधुनिकता के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के लिए चुनौती है। इकाई में इसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार गिड्डन और आधुनिकीकरण सिद्धांतों के अन्य समर्थकों ने अपने सिद्धांतों का बचाव किया और उत्तर-आधुनिकता की तुलना में उन्होंने सहवर्ती आधुनिकता के विचार को तरजीह क्यों दी। इकाई के अंत में आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के बीच के अंत: संबंधों की विश्लेशषण पर चर्चा की गई।

5.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

दुबे, एस.सी. (1988) आधुनिकीकरण और विकास। विस्तार पब्लिकेशन : नई दिल्ली।

रिज़र, जार्ज (2000), आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत। पांचवां संस्करण। मैकग्रा हिल हाईअर एडुकेशन।

सिंह, वाई. (1977) भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। थॉमसन, फरीदाबाद।

इकाई 6

विकास का उदारवादी परिप्रेक्ष्य

इकाई की रूपरेखा

6.1 प्रस्तावना

6.2 विचारधारा के रूप में उदारवाद

6.3 उदारवादी विचारधारा की शाखाएँ

6.4 उदारवादी राज्य का क्रम-विकास

6.5 सामाजिक असमानता का समाधान

6.6 कल्याणकारी राज्य

6.7 नव-उदारवाद का उद्‌गम

6.8 उदारवादी संदर्भ की समालोचना

6.9 सारांश

6.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.1 प्रस्तावना

यूरोपीय ज्ञान से उत्पन्न उदारवाद का विकास 19वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ। वर्तमान समय में उदारवाद को आधुनिक राजनीति की सर्वाधिक प्रभावी विचारधाराओं में गिना जाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेन, फ्रांस और अंग्रेजी लेखकों ने नकारात्मक अर्थ में किया था।

सुधारवादी और प्रगतिवादी विचारधारा के रूप में इसका प्रयोग जनता के लिए किया गया। शीघ्र ही इसे अपने नकारात्मक अर्थ से मुक्ति मिल गई और यह एक आदर्शसूचक राजनीतिक शब्द बन गया। अब अधिकतर लोग स्वयं को ''उदार'' कहलाना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ है– ''मुक्त/स्वच्छंद विचारों वाला व्यक्ति'', ''सहृदय या उदार और सहनशील व्यक्ति'', ''लोगों के कल्याण के लिए अपने हितों का त्याग करना'', ''निष्पक्ष एवं तार्किक दृष्टि से प्रत्येक मुद्दे का समाधान करना'' और ''पूर्वाग्रह तथा अंधविश्वास'' को न मानने वाला व्यक्ति। इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी कानून और इस कानून को व्यवहार में अपनाने का विरोध करते हैं, जो किसी विशेष सामाजिक समूह को लाभों से वंचित रखता है। उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थक वाक् स्वतंत्रता, विरोध और धरना देने के अधिकार और महिलाओं, समलैंगिकों, कैदियों, शरणार्थियों के अधिकारों का समर्थन करते हैं।

इस इकाई में हमने उदारवादी परिप्रेक्ष्य से विकास की संकल्पना को समझने का प्रयास किया है। हम उदारवाद की मूल विचारधारा, व्यापार के ऊपर आर्थिक एवं राजनीतिक नियंत्रण के रूप में राज्य द्वारा शक्ति के साथ हस्तक्षेप और उदारवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका से शुरू करते हुए उदारवादी परिप्रेक्ष्य की समीक्षा और नव उदारवाद पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम उदारवादी परिप्रेक्ष्य से विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भूमिका या संरचना का निर्माण करते हुए अपना अध्ययन समाप्त करेंगे।

6.2 विचारधारा के रूप में उदारवाद

उदारवाद ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए एक विशेष परिप्रेक्ष्य प्रदान

किया है। इसने एक ऐसी विचारधारा प्रस्तुत की है, जिसने इतिहास को स्वरूप प्रदान किया है और वर्तमान में मानव के भविष्य को प्रभावित करने के लिए नव-उदारवाद के रूप में फिर से जन्म लिया है। पिछले दो सौ वर्षों में मानव का इतिहास एक प्रकार से आर्थिक उदारवाद के समर्थकों 'स्व-नियामन बाजार' के सिद्धांत के प्रति समर्पित और "समाज का बचाव करने वालों (जिन्होंने मुद्रा बाजार का नियमन करने की वकालत की) के बीच एक संघर्ष का इतिहास रहा है। इस संघर्ष का राजनीतिक और वैचारिक क्षेत्रों में विस्तार हुआ। दोनों परस्पर विरोधी परिप्रेक्ष्यों ने अपनी-अपनी ठोस संकल्पनाएँ, सिद्धांत और विचारधाराएँ और तकनीकें प्रस्तुत कीं और सामाजिक संबंध में अपने दृष्टिकोणों के सामने रखा। 'लचीले' श्रम बाजार की विशेषताओं पर उपजा संघर्ष और आजीविका के लिए इसकी चुनौती निरंतर जारी रही। विकास के संबंध में अग्रणी परिप्रेक्ष्यवाद अर्थात मार्क्सवाद और उदारवाद के बीच सामाजिक असमानता की व्याख्या और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की विधि के बारे में उनमें मतभेद रहा है। बाजार कीमतों की संभावनाओं (scope) के मुद्दे पर तर्क-वितर्क किया गया। अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यहाँ पर प्रासंगिकता का प्रश्न यह है कि क्या बाजार की ताकतों को स्वतंत्र रूप से चलने के लिए छोड़ दिया जाए या उनके लिये भी कोई अधिनियम होना चाहिये। इसका अंतर यह है कि क्या विकास को उत्पादकता वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय तक सीमित किया जाए अथवा इसे आम जनता को सशक्त करने और उनको न्याय दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के रूप में व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए।

आदर्शत: उदारवाद दो शताब्दियों से समाजवादी आदर्श (ideals) का विरोध कर रहा है। यह हमें समाज, स्वतंत्रता और आर्थिक उद्यमिता के क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता, उत्पादन को नियंत्रित करने एवं स्वतंत्र नागरिकता को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका के बारे में विशेष दृष्टि प्रदान करता है।

एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद ने राजनीतिक निरंकुशता (absolutism) के किसी भी रूप का विरोध किया है, चाहे वह राजतंत्र हो, सामंतवाद हो, सैन्यवाद हो या साम्यवाद (communism) हो। यह एक ऐसे सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण का पक्षधर है, जिसमें प्राधिकरण या कुछ लोगों के हाथ में शासन की बागडोर पर प्रतिबंध लगाने और निजी संपत्ति का अधिकार, किसी भी धर्म में आस्था रखने, अभिव्यक्ति और संघ बनाने की स्वतंत्रता व्यक्तियों और समूहों के मौलिक अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है।

पारम्परिक (क्लासिकी) उदारवाद की दार्शनिक आधारशिला को डेविड ह्यूम, जेरमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल की कलम से संरचना प्रदान की गई। इन विचारकों ने इस आधार पर सामाजिक संपर्क सिद्धांत का निर्माण किया कि मानव का मार्गदर्शन बौद्धिक स्वअभिरुचि, तार्किकता और स्वतंत्र विकल्प से होता है और स्वतंत्र रूप से विकास की विचारधारा ऐसे स्वतंत्र वातावरण में उत्पन्न होती है, जिस पर राज्य का कम से कम नियंत्रण हो। उदारवाद, अस्तक्षेप की नीति (laissez-faire) के आर्थिक सिद्धांत में शामिल मार्गदर्शी सिद्धांत था, जिसका अर्थ है—उत्पादन और व्यापार में उद्यमिता का स्वतंत्र रूप से संवर्धन करना। यह स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का पथ-प्रदर्शक भी है।

6.3 उदारवादी विचारधारा की शाखाएँ

आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विचारों की उदारवादी शाखा अखंडित (monolithic) नहीं है, बल्कि इसमें उदारवादी विचारों की भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं, जिनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राज्य का प्रश्न विशेष महत्व रखता है।

बॉक्स 6.1: उदारवाद को प्रभावित करने वाले प्रमुख सिद्धांत

उदारवाद कभी भी एक एकीकृत (unified) और संगत (consistent) सिद्धांत नहीं रहा है बल्कि यह विभिन्न सिद्धांतों का संगम रहा है, जिसमें Recht Staat, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बुनियादी अधिकारों की रक्षा, प्रतिनिधि-सरकार, शक्ति पृथक्करण, राज्य की सीमित भूमिका, तार्किक व्यक्तिवाद और पूँजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था शामिल हैं (टॉरफिंग 1999 : 249)।

कुछ उदारवादी आर्थिक स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते हैं और नैतिक जीवन में सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। (थेचरवाद और रीगनवाद में सन्निहित राजनीतिक दार्शनिकता को इसके एक उदाहरण के रूप में लिया गया है) जबकि कुछ विद्वान जीवन के विभिन्न कार्यों के राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। इस बाद वाली सैद्धांतिक विचारधारा को प्राय: उदारवाद कहा जाता है।

उदारवाद का मूल सत्रहवीं शताब्दी के अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक जॉन लॉक की रचनाओं में है, जिन्होंने व्यक्ति के जीवन (प्राण), स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार और राज्य के उस कठोर हस्तक्षेप को समाप्त करने पर जोर दिया, जो स्वतंत्रता का सबसे अधिक उल्लंघन करता है। इसके बावजूद व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षणवादी विचारों का एक सुगम चिन्हक (marker) है (ब्रिटिश संरक्षणवादियों और अमेरिकी उदारवादी दलों की मार्गदर्शी विचारधारा)। अमेरिका के दार्शनिक रॉबर्ट नौजिक (Robert Nozick) (1974) और अर्थशास्त्री फेडरिक हेक (Fedrich Hayek) अपने-अपने क्षेत्र के उदारवाद के आधुनिक समर्थकों में से हैं। नोजिक राज्य की भूमिका को केवल नागरिकों की 'संरक्षक एजेंसी' तक सीमित करने के पक्ष में थे। हेक (1944, 1982) का मानना था कि आदर्श आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था और परस्पर-वैयक्तिक संबंध बाजार-विनिमय के मॉडल हैं, सरकार की भूमिका व्यवस्था बनाए रखने और ऐसी जन-सुविधाएँ/सेवाएँ उपलब्ध कराना है, जिसमें शुरू में अधिक पूँजी-निवेश की जरूरत हो। उदारवादी आदर्श को संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक सहयोग मिला, उसमें संरक्षणवाद ओर नव-उदारवाद को आसानी से समाहित किया जा सकता है। इस प्रकार उदारवाद मनुष्य से ऐसी कार्रवाई की अपेक्षा करता है जिसका मार्गदर्शन किसी भी प्रकार की नियतिवाद (determinism) से न किया गया हो।

आमतौर पर उदारवादी मान्यताएँ समाजवाद और संरक्षणवाद की मान्यताओं से मेल नहीं खाती हैं। टॉम पेनी (Tom Paine) का चरम उदारवाद, अर्थव्यवस्था में सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप की विचारधारा पर आधारित था, जो समाजवाद के निकट था जबकि अन्य उदारवादियों की निजी संपत्ति के अधिकार की दृढ़ संकल्पना उन्हें संरक्षणवाद के निकट ले जाती है। पेनी और अन्य का प्रारंभिक उदारवाद, प्रगतिवादी था क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्ति को परम्परागत राजनीतिक बाधाओं से मुक्त कराना था। वे चाहते थे कि सरकार की भूमिका सीमित हो। जॉन लॉक के शब्दों में, सरकार का काम एक निर्णायक (अम्पायर) की भूमिका को निभाना है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए निष्पक्षता से काम करे। इस प्रकार यह विश्वास किया गया कि नागरिकों को अपने भविष्य को सँवारने के लिए अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान किए जाएँगे।

अभिजात तंत्र की शक्ति के समाप्त होने के बावजूद भी उदारवाद प्रगतिवादी सामाजिक प्रवृत्तियों से जुड़ा रहा। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के बाद उदारवादियों ने सरकारी पहल की वृद्धि को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। अब उदारवादियों का तर्क था कि गरीबी और बेरोजगारी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी आई है और अनियंत्रित हस्तक्षेप, अहस्तक्षेप के कारण उत्पन्न पूँजीवाद इसका मूल कारण है। इसलिए सरकार को बड़े पैमाने पर सामाजिक हस्तक्षेप और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आर्थिक प्रतिबंधों का उन्मूलन करने के लिए व्यापक भूमिका निभानी होगी।

उदारवादियों का हमेशा यह विश्वास रहा है कि व्यक्तिगत व्यवहार पर राजनीतिक और आर्थिक बाधाओं को हटाने से समाज के आचरण में सुधार आएगा। इस दृष्टिकोण के अनुसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक प्रगति की कुंजी है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता से रहने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भरता, मितव्ययता, सहिष्णुता और दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान जैसे गुणों को अर्जित करता है। इन गुणों को आमतौर पर बुर्जआ (मध्यम वर्ग) कहा जाता है, क्योंकि पूँजीवादी समाज में इन गुणों का प्रदर्शन/व्यवहार आर्थिक रूप से सफल समूहों द्वारा किया जाता है।

उदारवाद, पूँजीवादी विश्व की प्रगति से संबद्ध रहा है। इसके समर्थक आर्थिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए व्यक्ति की क्षमता को प्रतिबंधों से मुक्त रखने के पक्षधर हैं। उनका तर्क था कि पूँजीवादी व्यवस्था से जुड़ी आर्थिक स्वतंत्रता भी एक प्रकार से नैतिक स्वतंत्रता को जन्म देती है। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि उदारवादियों ने मध्यम वर्ग (embourgeoisment) की प्रक्रिया का पक्ष लिया है, जिसमें अंतत्वोगत्वा प्रत्येक व्यक्ति सहयोगी अर्थव्यवस्था के अनुकूल मनोवृत्ति स्वीकार करेगा।

उदारवाद का इतिहास अधिकारों का विस्तार करने के लिए कार्यनीतियों के अनुक्रम को व्यक्त करता है, जिसे व्यक्तियों की आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की कार्यनीति माना गया है। उदारवाद के विभिन्न रूप एक ऐसे एकवर्गीय समाज की कल्पना करते हैं, जिसमें स्वयं पर शासन करने वाले नागरिक शामिल हों। समुदाय का उदारवादी आदर्श वह है, जिसमें संपत्ति में असमानता के बावजूद स्व-अनुशासन और एक-दूसरे के लिए सम्मान की भावना को प्राथमिकता दी जाती है।

6.4 उदारवादी राज्य का क्रम-विकास

उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लैंड में वाणिज्यिक हितों ने राज्य की शक्तियों को सीमित करने और ऐसे प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें व्यावसायिक गतिविधियाँ अबाधित रहें। राज्य ने 'सहयोग' का प्रस्ताव किया और जनहित में पूँजीपतियों के आंदोलन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उदारवादी राज्य इस अवस्था में अहस्तक्षेप राज्य नहीं था, बल्कि ऐसा राज्य था जिसमें व्यक्तिगत रूप से संपत्ति इकट्ठा करने के लिए परिस्थितियों का सृजन करने और उन्हें बनाए रखने के लिए हस्तक्षेपवाद की आवश्यकता थी। इसने सार्वजनिक जीवन में मध्यम वर्ग की सक्रियता की माँग भी की।

पूँजीवाद के विस्तार ने राज्य की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित पहले से चली आ रही वाणिज्यवादी संकल्पना और व्यापार पर राजनीतिक नियंत्रण को कम करने का प्रयास किया। इसके स्थान पर आर्थिक मामलों पर जनता के कार्यों में मुख्यतः कानूनी, वित्तीय, मौद्रिक और कामों के साथ-साथ भूमि, पूँजी और श्रम बाजार द्वारा निर्मित आवंटन-कार्यनीति के स्वायत्त स्वनिगमित संचालन के लिए वित्तीय ढाँचागत कार्य शामिल थे (पॉगी 1978 : 115)। इस प्रकार उदारवादी राज्य ने अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन दोनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। वोल्फ (1997) का सुझाव था कि "विस्तार के इस काल में राज्य की संग्राहक की भूमिका थी—आर्थिक गतिविधियों के व्यापकतम प्रतिमानों को परिभाषित करना, उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुशासन कायम करना, सूक्ष्म-आर्थिक स्थितियों का समायोजन करना, निजी उद्योगों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना और युद्ध का सामना करना। इसके साथ ही, ब्रिटेन में नया मध्यम वर्ग ऐसे सामाजिक नियंत्रण के विद्यमान स्वीकृत रूप में सुधार लाने और इसे एकीकृत करने के लिए संसद में पहुँच गया, जो विकासशील पूँजीवादी समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं थे।

समानता और नागरिक अधिकारों की अवधारणा ने उदारवाद में व्यक्तिवादी आस्था के बावजूद सुविधावंचितों और मताधिकार से वंचितों को अपनी माँगों और भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आबादी के एक बड़े समूह द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मांग से एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली में व्यवसाय के साथ संभावित संघर्ष का जन्म हुआ, जिसमें सरकार की शक्ति मताधिकार से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अंतिम विश्लेषण में, लोकतंत्रीकरण पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक के रूप में नहीं आया। इसने ताकतों के एकीकरण में सहायता की (विशेष रूप से कामकाजी वर्ग), मार्क्स के अनुसार जिसने पूँजीवादी व्यवस्था के विघटन को बल दिया।

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान, औपचारिक उदारवादी अधिकारों के विस्तार ने गहरी होती सामाजिक असमानताओं के सहयोजन के साथ समानता के प्रश्न पर चर्चा को अधिक बल दिया। यूरोप के अनेक देशों में अहस्तक्षेप की विचारधारा के समर्थकों के विरोध के बावजूद संघ और ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार का कामकाजी (श्रमिक) वर्ग तक विस्तार किया गया, जिससे सामाजिक न्याय को व्यापक बनाया जा सके। निम्न वर्गों तक नागरिकता का विस्तार करने को विशेष अर्थ दिया गया कि नागरिक के रूप में इन वर्गों के सदस्यों के कल्याण के लिए कुछ सहूलियतें दी गईं, जिससे वे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें (बेनडिक्स 1964)। इस प्रकार के कार्यों से उदारवादी राज्य की उग्र व्यक्तिवाद की धारणा में बदलाव आया। लेकिन आधुनिक और निरंतर शक्तिशाली राज्य के उद्‌भव से उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में, राज्य द्वारा बाजार में हस्तक्षेप क[illegible]ापूर्वक पूँजी इकट्ठा करने के सक्रिय और सुनिश्चित कार्रवाई के प्रति व्यापारियों ने विरोध प्रकट किया। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में, उदारवाद के प्रतिमान में संकल्पित मॉडल पर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाई। फर्मों का आकार बड़ा था, उत्पादन केंद्रित था, देयता अधिक स्पष्ट थी और व्यापारिक स्वामित्व का संचालन एवं प्रबंधन और अधिक स्पष्ट हो गया था और विदेशों से प्रतियोगिता बढ़ने के कारण घरेलू-बाजार के संरक्षण की मांग की गई। प्रथम विश्व युद्ध ने पूँजीवाद की संरचना को इस प्रकार से बनाया जो उदारवादी संरचना से एकदम अलग थी। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में युद्ध के अंत तक राज्य ने संयुक्त रूप से रेलवे पर नियंत्रण कर लिया, लाभ को सुनिश्चित किया और बीमा क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई। यह सबसे बड़ा नियुक्ता बन गया। राष्ट्रीय उत्पाद के अधिकांश हिस्से का उत्पादक और निर्माता बन गया। दोनों विश्व युद्धों के बीच के समय में राज्य और व्यापारिक हितों के बीच में सहयोग सामाजिक प्रबंध का महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका दोनों में कल्याणकारी राज्य की ओर स्पष्ट झुकाव नजर आने लगा।

6.5 सामाजिक असमानता का समाधान

उदारवादी विचारक यह स्वीकार नहीं करते थे कि असमानता समाज में अंतर्निहित होती है बल्कि वे इसे समाज द्वारा निर्मित मानते थे। इस प्रकार, असमानता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे दूर किया जाना चाहिए। चूँकि व्यक्ति स्वतंत्र और समान रूप से जन्म लेता है, इसलिए राज्य को उनकी सहमति से चलाया जाना चाहिए जिनके अधिकार से राज्य बनता है। संरक्षणवादियों के साथ उदारवादी समाजवादी समानतावाद (equalitarism) के प्रति अरुचि रखते हैं। ये दोनों ही एक ऐसी स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता का समर्थन करते हैं जिसमें व्यक्तिगत योग्यता और उद्यम को समुचित सम्मान मिले। उनके अनुसार पुरस्कार (सम्मान) एक-जैसा होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति अपने भौतिक सुख के लिए समान दक्षता और प्रयास करता है। वे समाजवादियों की उस विचारधारा को खारिज करते हैं जिसमें वे व्यक्ति को उसकी योग्यता की अपेक्षा उसकी आवश्यकता के आधार पर पारितोषिक देना चाहते हैं। उदारवादी इसे अन्याय मानते हैं। सामाजिक समानता के लिए न तो संरक्षणवादी और न ही

उदारवादी स्वतंत्रता का बलिदान करना चाहते हैं। असमानता के प्रश्न पर उदारवादियों की स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है:

उदारवादी समाज कभी भी समतावादी समाज नहीं हो सकता, चूँकि स्वतंत्रता में आगे बढ़ने या पीछे लौटने की स्वतंत्रता शामिल है और उदारवादी विलासिता के हित में कभी भी विरोध करने को सहमत नहीं हो सकते। इसके विपरीत हमें अवसर की समानता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे निहितार्थों को स्वीकार करना चाहिए कि अवसर प्राप्त व्यक्ति धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाता है जबकि इससे वंचित व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता (वाटसन 1957 : 192)।

लेकिन आधुनिक उदारवादी, समाजवादियों के साथ थोड़ा-बहुत पुन:वितरणात्मक न्याय को बनाए रखने की आवश्यकता महसूस करते हैं। उनका मानना है कि असमानता से ऐसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है, जो जीवन की कठिनाइयों और गरीबी से जूझ रहे हों, इस कारण से, वे सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं। वे इससे भी सहमत हैं कि लोगों का कल्याण करना एक प्रकार से स्वतंत्रता का ही एक रूप है, जहाँ तक यह मनुष्य को ऐसी सामाजिक परिस्थितियों से स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो उनके विकल्पों को अवरुद्ध करती हैं और उनके स्व-विकास को रोकती हैं। इस प्रकार उनके अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा अधिक से अधिक एक-जैसे समाज की रचना करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने की बजाय उनकी सुरक्षा करने का प्रयास करता है। असमानता के प्रश्न पर विचार करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि उदारवादी दुविधा की स्थिति में होते हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के नियंत्रण दोनों को ही चाहते हैं, जिसे स्वतंत्रता की एक पूर्व-शर्त माना जाता है।

6.6 कल्याणकारी राज्य

उदारवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका में अंग्रेजी अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स (1883-1946) की प्रभावी रचनाओं के बाद नया रूप ग्रहण किया। केन्स ने इस आधार पर उदारवादी विचारधारा का विरोध किया कि अनियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है और इस प्रकार सामाजिक संतुलन और स्थायित्व को प्राप्त किया जा सकता है। ''राज्य की नगण्य भूमिका'' के हस्तक्षेप की नीति से हटकर केन्स (1936) ने तर्क दिया कि इस बिंदु पर पहुँचने से पहले संतुलन कायम किया जा सकता है अर्थात् समाज व्यापक माँग और राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप से पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि पूर्ण रोजगार से मुद्रास्फीति का जन्म होता है, तो राज्य को व्यापक मांग को कम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में सरकार का हस्तक्षेप (राजकोषीय) नीति, सरकारी खर्च और मौद्रिक नीति (ब्याज दरों में परिवर्तन और क्रेडिट की आपूर्ति) पर नियंत्रण के रूप में होनी चाहिए। सन् 1930 के दशक की महा मंदी (depression) ने पूँजीवादी विश्व को तहस-नहस कर दिया और इस मंदी से बाहर निकलने के असफल प्रयास में इसने राज्य की शक्तियों का निर्माण करने और उन्हें लागू करने के लिए नये रास्तों की तलाश की (हार्वी 1989 : 128)। केनवादी अर्थव्यवस्था ने राज्य को मांग का प्रबंध करने और बड़े पैमाने पर उपयोग सुनिश्चित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपा। इस 'नई संकल्पना' को नये कल्याणकारी राज्यों ने व्यवहार में अपनाया। इन कल्याणकारी राज्यों की स्थापना उन उपलब्धियों पर निर्भर थी, जो वर्षों के संघर्ष के बाद बड़े कार्पोरेट क्षेत्रों, संगठित श्रमिकों और राज्य के बीच शक्ति संतुलन के बाद प्राप्त की गई थी। केन्सवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् कम से कम तीन दशकों तक उदारवादी आर्थिक विचारों और आर्थिक नीतियों पर अपना वर्चस्व कायम किया। अधिकतर पश्चिमी देशों की आर्थिक नीतियाँ रोजगार के अवसर सृजित करने और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, नागरिक सुविधाएँ और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को अनुशासित

कर प्रणाली द्वारा प्राप्त करने के पक्ष में थीं। केन्सवाद से उत्पन्न विकास नीतियों ने पश्चिमी पूँजीवाद को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से समेकित करने में सहायता की। आंतरिक रूप से, समाज के कमजोर वर्गों को उदारवादी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में एकीकृत किया गया जबकि बाह्य रूप से पश्चिमी पूँजीवादी विश्व ने समाजवादी ब्लॉक के समक्ष अपनी स्थिति को मजबूत किया। इस प्रकार, बीसवीं शताब्दी के दूसरे पक्ष में विकसित औद्योगिक समाजों में आम जनता के कल्याण की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य की भूमिका में वृद्धि हुई और इसने सामाजिक स्थायित्व के लिए सुविचारित नीति बनाई।

> अभ्यास 6.1
> आपकी राय में राज्य को किस सीमा तक व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए?

6.7 नव-उदारवाद का उद्गम

युद्ध के बाद के समय में, यद्यपि पश्चिमी राज्य लोक नीति में कल्याण के महत्त्व को एक तत्त्व के रूप में महसूस कर रहे थे लेकिन साथ ही प्रौद्योगिक और पूँजी के मुक्त रूप से हस्तांतरण को सुगम बनाने में राज्य की भूमिका में शिथिलता की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। प्रतिष्ठित नव-उदारवादी, उदारवादी थे और व्यक्ति के ऐसे अधिकारों के प्रबल समर्थक थे जो कभी-कभी कठोर राज्य का विरोध करते थे। इसके प्रमुख संरक्षकों में मिल्टन, फ्रायडमैन, फ्रैडरिक हायक और रॉबर्ट नोजिक शामिल हैं। उदाहरण के लिए, फ्रेडरिक ए. हायक को उनके केनियन विरोधी मोनेटेरिज्म (monetarism) के लिए जाना जाता है। अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के प्रबल समर्थक हायक (1944) का तर्क था कि केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है और इस प्रकार कृषि दासता (serfdom) के लिए परिस्थितियाँ पैदा करती है। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि सामूहिकवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक खतरा है (देखें हायक 1982)।

अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित पारम्परिक (क्लासिकीय) उदारवाद की विचारधारा 1980 के दशक में उत्पादन, वितरण और उपभोग की व्यवस्था के उदारीकरण और भूमंडलीकरण के रूप में फिर से प्रकट हुई। पिछले दो दशकों में कई पश्चिमी समाजों, विशेष रूप से 1980 के दशक में अमेरिका में रीगनवाद और इंग्लैण्ड में थैचरवाद में राज्य की कल्याण नीतियों में कमी आई है और इसमें कल्याणकारी योजनाओं का निजीकरण हुआ है तथा आवश्यकता की तुलना में भुगतान करने की क्षमता की विकास हुआ है।

बीसवीं शताब्दी के अंत में, उन्नीसवीं शताब्दी की तरह ही राजनीति की एक मुख्य लड़ाई आर्थिक उदारवाद के समर्थकों और 'समाज के संरक्षण' के लिए हस्तक्षेप के समर्थकों के बीच लड़ी गई। बाद में एक बार फिर से संरक्षणवाद के समर्थकों को अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। यह तथाकथित 'तीसरा विकल्प' (third way) का सार है, जिसके बारे में 1990 के दशक में व्यापक चर्चा की गई। इनकी स्थिति या मान्यता पूर्ववर्ती समाजवादियों के समान थी और इसने यूरोप में नए चुने गए वाम केंद्र नेताओं (left center leader) - इंग्लैण्ड में टोनी ब्लेयर, फ्रांस में लियोनेल जोसपिन, जर्मनी में गेरहर्ट शोर्डर और अमेरिका में क्लिंटन को एक साथ इकट्ठा किया। 'तृतीय विकल्प' को पूँजीवाद में व्यापक रूप से वृद्धि के प्रभाव को कम करने के संतुलित प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया। औद्योगिकरण, विकास की पूर्व शर्त है, जिसे आर्थिक प्रगति, परंपरागत मूल्यों की समाप्ति, तार्किकता में वृद्धि बड़े पैमाने पर गरीबी उन्मूलन, स्वतंत्रता और नागरिकता के प्रचार-प्रसार के रूप में देखा जाता है।

समाजविज्ञानी विकास के नव-उदारवादी चरण के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति चिंतित है। कैसेल (1996) का तर्क है कि पूँजीवादी वृद्धि के नये युग में ध्यान औद्योगिकरण से सूचना और ज्ञान के नेटवर्क की तरफ चला जाएगा। 1998-99 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि "धनी और निर्धन देशों में ज्ञान सृजन के कुछ महत्त्वपूर्ण उपायों में अंतर आय की तुलना में बहुत अधिक है।" निश्चित रूप से औद्योगिक देशों में विनिर्माण क्षेत्र में कमी और सेवा तथा ज्ञान आधारित क्षेत्रों में विकास से भविष्य में विकासवादी विश्लेषकों और नीति-निर्माताओं के समक्ष नई समस्याएँ उत्पन्न होंगी।

नव-उदारवादी विकास की समालोचना को आगे बढ़ाते हुए, किचिंग (1989) ने कहा कि, "विकास एक डरावनी प्रक्रिया है, कोवेन और शेंटन (1996) के लिए विकास का अर्थ है—"प्रगति की अव्यवस्थित कमियों में सुधार करना।" विकास के अधिकतर प्रयास गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण और सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने में लग जाते हैं। 'विकास' को प्रायः गरीब समुदायों अथवा विस्थापित आबादी की सहायता और कल्याण कार्यक्रमों का द्योतक माना जाता है।

भूमंडलीकरण की देखरेख करने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां (विशेष रूप से विश्व बैंक) अब विश्व प्रणाली में गरीब समुदायों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। सामाजिक वैज्ञानिक वैश्विक एकीकरण को प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाने में लगे हैं। उदाहरण के लिए, चैम्बर्स (1989) ने लोगों के लिए बनाई विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी को सुगम बनाने और इस प्रक्रिया में उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए सहभागी उपागम का सुझाव दिया था। आज के वृहद वैश्विक नेटवर्क अथवा "सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन" (पी.आर.ए.) अथवा "सहभागी अधिगम (सीखना) और कार्रवाई" (पी.एल.ए.) के संवर्धन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं। इसमें गरीब समुदायों को अपने विकास की परियोजनाओं को अभिकल्पित करने और चलाने के लिए "छड़ी को उन्हें सुपुर्द करने" जैसे आदर्श विचार भी शामिल हैं। भारतीय संदर्भ में हम देखते हैं कि आर्थिक उदारीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सहभागी विकास जैसी प्रक्रियाओं को साथ ही साथ प्रयोग के रूप में अपनाया जा रहा है।

6.8 उदारवादी संदर्भ की समालोचना

सी.बी.मैकफर्सन (1966) ने इस आधार की आलोचना की कि यह "स्वत्वात्मक व्यक्तिवाद" का संवर्धन करता है। इसका अर्थ है— न्यूनतम सामाजिक और सहयोग देने वाला व्यक्ति। उदारवादी परिप्रेक्ष्य की समाजवादी समालोचना, असमानता और सामाजिक न्याय की व्याख्या पर आधारित है। यह तर्क दिया गया है कि असमानता की पक्षधर आर्थिक व्यवस्थ मुक्त बाजार प्रतियोगिता के वातावरण में असमानता और सामाजिक अन्याय में और वृद्धि करेगा। पारम्परिक (क्लासिकी) उदारवाद की समालोचना उदारवादी विचारधारा के समर्थकों ने भी की है। उदाहरण के लिए, केन्स ने रिकॉर्डो, मिल और बेंथम जैसे क्लासिकी उदारवादियों की आलोचना की है और कामकाजी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए राज्य-कल्याणवाद का सुझाव दिया है। समाजशास्त्रियों ने वैयक्तिक स्वायत्ता की विचारधारा की आलोचना की और इसे व्यर्थ बताया, उन्होंने तटस्थ शासन की संभावना को भी अस्वीकार किया जो सबको समान अवसरों की समानता की गारंटी का संवर्धन करेगा और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है ऐतिहासिक रूप से, कभी भी ऐसी मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था नहीं रही है जो राज्य के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रही हो। यहाँ तक कि 1980 और 1990 के दशकों में नव-उदारवाद ने ठोस वापसी की, इसने राज्य-कल्याणवाद की विचारधारा को पीछे छोड़ दिया, ऐसे समय में नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था से पीड़ित लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए फिर से बातचीत शुरू की गई।

उदारवादी उपागम ने श्रम-नियंत्रण की व्यापक व्यवस्था की, जिसमें ''थोड़ा बहुत दमनकारी, अभ्यास, सह-विकल्प और सहयोग शामिल है, जिन सबको न केवल कार्य-स्थल पर बल्कि पूरे समाज में भी संगाठित होना होगा'' (हार्वी 1989 : 123) और प्रमुख विचारधारा का निर्माण कर इसका समर्थन किया जाना है। विश्व में पूंजीवाद को समेकित करने का उदारवादी उपागम बोयर के पदबंध (1990) ''संग्रहण की प्रणाली'' से गुजरा है। बोयर के अनुसार ''संग्रहण प्रणाली'' एक ऐसी नियामक व्यवस्था है जो सामान्य और पूजी संग्रहण की अपेक्षाकृत समवर्ती प्रगति को सुनिश्चित करती है अर्थात् ऐसी प्रणाली जो विरूपण और असमानता के स्थगन संबधी संकल्प को स्वीकार करती है और जिसके लिए प्रक्रिया सतत जारी रहती है (बोयर 1980 : 35) लिपेट्ज लिखते हैं कि ''संग्रहण-प्रणाली'' मजदूरी कमाने वालों के पुनर्निमाण की दोनों स्थितियों के रूपांतरण के मध्य उत्पाद के आवंटन को लम्बे समय तक स्थिर करती है। इस प्रकार संग्रहण-प्रणाली सभी सामाजिक अभिकर्मकों या एजेंटो के कार्यकलापों का संयोजन है दूसरे शब्दों में, मानकों, आदर्तों, कानूनों, नेटवर्कों के नियमन आदि का संस्थानीकरण है, जो प्रक्रिया की एकता को सुनिश्चित करता है। अंत:कृत नियमों और सामाजिक प्रक्रिया का यह स्वरूप विनियमन का माध्यम कहलाता है।'' (लिपेट्ज सी.एफ. हार्वी 1989 : 122)। इस प्रकार उदारवादी उपागम ने अर्थव्यवस्था की न्यायसंगत और पुनरुत्थान की व्यापक व्यवस्था के साथ एक कानूनी और सामाजिक व्यवस्था कायम की जिसने स्व-नियमित अर्थव्यवस्था अथवा उदारवादी अर्थव्यवस्था के पुनर्निमाण को सुगम बनाने में मदद की।

मुक्त बाजार में अर्थव्यवस्था की सफलता राज्य की शक्ति को कम करके संभव नहीं थी बल्कि इसकी सफलता में राज्य के संरक्षण में व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था और श्रम शक्ति के प्रबंधन की व्यापक व्यवस्था शामिल थी। होलिंग्सवर्थ और बोयर (1997 : 2) ने विधि को ''उत्पादन की सामाजिक प्रणाली'' कहा था।

एंटोमनियो ग्राम्स्की के आधिपत्य और फॉकल्ट के जीव-शक्ति की विचारधारा को उदारवाद की समालोचना के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।

बॉक्स 6.2: आधिपत्य

आधिपत्य का अर्थ है नेतृत्व, प्राधिकार या एक राज्य या सामाजिक समूह द्वारा दूसरों के ऊपर प्रभुत्व कायम करना। इसमें प्रभुत्वसंपन्न राज्य या सामाजिक समूह द्वारा स्वयं को या स्वयं की विचारधारा को दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास किया जाता है, जिसका उनके द्वारा विरोध किया जाता है, जिन पर इसे थोपा जाता है।

पिछली दो शताब्दियों में उदारवाद, पश्चिमी पूँजीवाद की आधिपत्ययुक्त विचारधारा के रूप में सामने आया है। व्यापारिक घरानों के हितों से किसी प्रकार का समझौता किए बिना, पश्चिमी देशों ने गरीब एवं सीमांत लोगों को पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में शामिल करने के लिए अधिक से अधिक लोकतंत्रीकरण और उनकी सहभागिता पर जोर दिया। ग्राम्स्की और अल्थुजर का सुझाव था कि वर्ग-शक्ति के वैचारिक एकीकरण के लिए पश्चिमी राष्ट्रों ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम किया।

आधुनिक उदारवादी राज्य के कार्य की समालोचना में मिखाइल फॉकल्ट (देखें डीन 2001) ने तर्क दिया है कि शासन करने का अर्थ अब ऐसी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादन करना, सहायता देना और काम करना है जिसे इसे प्रभुत्वशाली व्यवस्था में सरकार की संस्थाओं के बाहर देखा जा सकता है। ये प्रक्रियाएँ जिन प्रभावशाली क्षेत्रों में निर्मित हुई हैं, उनमें से एक प्रभावशाली क्षेत्र ''जैव-राजनीतिक'' है। जैव-राजनीतिक, विशेष रूप से जैसी यह आबादी के स्तर पर दिखाई देती है, जीवन के प्रशासन की राजनीति से संबंधित है। इस प्रकार जैव-राजनीति

को सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, जिसमें मनुष्य रहता है, संरक्षित होता है, अस्वस्थ होता है, स्वास्थ्य को बनाए रखता है, स्वस्थ बनता है और मृत्यु को प्राप्त होता है।

फॉकल्ट ने लोगों को अधिक से अधिक स्वायत्तता देने और आर्थिक प्रबंध से शासन करने की निरपेक्ष शक्ति द्वारा शासन से शासन की क्रियाविधि के संक्रमण के इतिहास का वर्णन किया है। तब जैव-राजनीति, नागरिक समाज में व्यापार की भूमिका के साथ राजनीतिक तार्किकता और विशिष्ट ज्ञान के संपर्क में आती है। फॉकल्ट के अनुमान से 19वीं शताब्दी के प्रथम पच्चीस वर्षों में पारम्परिक (क्लासिकी) अंग्रेजी राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने जनसंख्या के जीवन में आशा उत्पन्न करने पर ध्यान दिया। उदाहरण के लिए, थामस माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया और मानव जीवन की निरंतर बढ़ती गुणवत्ता के निर्वहन की प्राकृतिक प्रक्रिया के बीच के संबंध तथा अभाव और आवश्यकता के बीच के संपर्क की खोज की। अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभिक अंग्रेजी राजनीतिक अर्थशास्त्रियों द्वारा खोजी गई जैव-आर्थिक वास्तविकताओं और उनके कार्यों ने जनसंख्या के जीवन की प्रत्याशा को अधिक से अधिक सार्थक करने के लिए शासन के नये मानकों को बनाने में सहायता प्रदान की। ये नये नियम सरकार को आर्थिक वास्तविकताओं, वाणिज्यिक समाज और बाजार के माध्यम से अधिकार प्रदान करते हैं। वे दक्षता से शासन करने, अपव्यय को रोकने और लागत को सीमित करने का भी निर्देश देते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे ''किफायती सरकार'' का नाम दिया था।

फॉकल्ट के अनुसार, उदारवाद को अतिवादी सरकार की समालोचना के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन, इसे न केवल पूर्ववर्ती सरकार की समालोचना के रूप में अर्थात् पुलिस और राज्य के कार्यकरण के रूप में देखा जा सकता है, बल्कि बायो-राजनीतिक सरकार के विद्यमान और संभावित रूप में भी देखा जा सकता है। इस प्रकार उदारवाद सरकार के ऐसे अन्य संभावित रूपों की आलोचना करता है जिन्हें जीवन प्रक्रिया में अपनाया जा सकता है।

फॉकल्ट के अनुसार उदारवाद सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करता था और ''सुरक्षा की व्यवस्था को उचित स्थान दिया, जिसका कार्य प्राकृतिक घटनाओं, आर्थिक प्रक्रियाओं, आबादी की अंतर्निहित समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करना सरकार का आदर्श उद्देश्य है। फॉकल्ट का सुझाव था कि उदारवादी राज्यों द्वारा नागरिकों की आर्थिक और जैविक सुरक्षा की एक शर्त के रूप में स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया था। उदारवाद में कानूनी और संसदीय संरचना को स्वीकार किया जाता है, इसका कारण न्यायिक विचारधारा से इसकी सन्निकटता है क्योंकि प्राय: कानून समान रूप से लागू होता है और इसमें विशेष और अपवाद शामिल नहीं होता। संसदीय प्रणाली द्वारा उदारवाद में शासित वर्ग को उदार सरकार में सहभागिता की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वास्तव में, फॉकल्ट यह सुझाव देना चाहते थे कि उदारवाद की मानकों से कानून की तुलना में अधिक सन्निकटता होती है। यही कारण है कि पहले इसने अत्यधिक शासन और न्यूनतम शासन के बीच में परिवर्तन-संतुलन में सुशासन के मानकों की सतत् माँग की और उसके बाद, इसने ऐसी प्रणाली लागू की जिसने विषयों को इस प्रकार से स्थिर और सामान्य बनाया जिससे वे स्वतंत्रता का प्रयोग उत्तरदायी ढंग से और अनुशासित होकर कर सकें।

इस प्रकार उदारवाद ने ''सामान्यीकरण के समाज'' की संकल्पना के रूप में अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया। इसने अर्थव्यवस्था, समाज और जनसंख्या की स्वायत्ता प्रक्रिया के लिए आवश्यक उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता के निर्माण पर बल दिया। उदारवाद ने फॉकल्ट की ''विभाजक व्यवहार'' (dividing practices) विभिन्न संदर्भों और विभिन्न शाखाओं के रूप में प्रयोग किया। फॉकल्ट के विभाजक व्यवहार का अर्थ है, जिसमें ''कर्त्ता स्वयं के भीतर

या दूसरों से विभाजित रहता है''। इसके साथ ही, उदारवाद का इतिहास बताता है कि किस प्रकार उदारवादी तकनीकों की शृंखला को उन व्यष्टियों और समष्टियों पर लागू किया जा सकता है, जिन्हें सुधार और स्व-शासन प्राप्त करने के लिए सक्षम माना जाता है (महिला और बच्चों से अपराधियों और कंगालों के कुछ वर्ग)।

फॉकल्ट का उदारवादी सरकार के निर्माण संबंधी जैव-राजनीतिक और प्रभुसत्ता के मुद्दों की जटिल अभिव्यक्ति का सुझाव देता है। यह गड़ेरिया झुंड (shephered folk) खेल के तत्वों की अभिव्यक्ति है जो अपने आधुनिक स्वरूप में समष्टि के जीवन की पहचान को अधिकतम बनाए रखने और व्यष्टि की पहचान को सामान्य बनाता है। शहर-नागरिक खेल, जिसमें व्यक्ति एक स्वशासी राजनीतिक समाज और व्यापारिक समाज में सक्रिय और उत्तरदायी नागरिक के रूप में दिखाई देता है। नागरिकों को अनुशासित और अधीन करने की क्रियाविधि में निपुणता द्वारा सफलता प्राप्त करने की इस संतुलित कार्रवाई में इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि करना था। जहाँ एक ओर उदारवादियों द्वारा अधिकारों और कानूनी संरचना की संकल्पना को लागू कर जीवन की प्रत्याशा को अधिकतम करने और जैव-राजनीतिक निहितार्थ को सुरक्षित करने का प्रयास किया और उसने इसे संप्रभुसत्ता के नियम से अपनाया, वहीं दूसरी ओर इसने ज्ञान के ऐसे स्वरूप के उद्भव को रोकने में स्थायी रूप से असमर्थ पाया जो दूसरों के जीवन की प्रत्याशा को अधिकतम बना सकता है।

अभ्यास 6.2

विकास के उदारवादी परिप्रेक्ष्य की प्रमुख सीमाएँ क्या हैं?

6.9 सारांश

विकास के परिप्रेक्ष्य के रूप में उदारवाद को इसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अर्थों के रूप में व्यापक स्वरूप में समझना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएँ, आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ मुख्यत: उदारवादी परिप्रेक्ष्य से प्रवाहित होती हैं। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद का इस्तेमाल पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की अबाधित वृद्धि और पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था के लिए किया जाता रहा है। विकास के उदारवादी परिप्रेक्ष्य की सामान्य विचारधारा इससे मुक्ति प्रदान करेगी कि शक्ति संबंध, कानूनी प्रक्रिया और सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्त्वों के प्रयोग ने किस प्रकार से विश्वभर में मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के विस्तार को बढ़ावा दिया। यद्यपि समानता, मौलिक अधिकार और न्याय की मान्यता के साथ सभी देशों में आम आदमी का अधिकाधिक लोकतंत्रीकरण और सशक्तिकरण हुआ, उदारवादी राज्यों ने अंतिम विश्लेषण में आवधिक संकटों के समय पूँजीवाद को संकटों से मुक्त कराया है और इसे फिर से मजबूत आधार प्रदान किया है। इस प्रकार, आधारिक अधिसंरचना संबंध के मार्क्सवादी प्रतिमान को फिर से लागू किया गया। शुद्ध अहस्तक्षेप नीति कभी भी व्यवहार्य नहीं रही है क्योंकि पूँजी को हमेशा ही राज्य से किसी न किसी प्रकार की सहायता की जरूरत रही है। राज्य ने ऐतिहासिक रूप से पूँजी की अबाधित वृद्धि के लिए कार्यनीतियाँ बनाई हैं और आदर्शवादी, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करने के लिए श्रमहारा वर्ग को पूँजीवादी समाज में सफलतापूर्वक उपयोग किया है। पिछले दो-तीन दशकों में उदारवाद ने नव-उदारवाद के रूप में पूरी मजबूती से अपनी फिर से मौजूदगी का अहसास कराया है और अब यह विश्व में व्यापक स्तर पर सक्रिय है। प्रमुख नव-उदारवाद एक उत्तेजक नई विचारधारा है और नया आंदोलन है जो कामकाजी वर्ग और पीड़ितों के संरक्षण का कार्य कर रहा है। इस प्रकर वैश्वीकरण की घटना और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक निहितार्थों को विश्व स्तर पर जाँचा-परखा जाना चाहिए।

यद्यपि पारम्परिक (क्लासिकी) उदारवाद की संरचना आर्थिक सिद्धांतवादियों द्वारा विकसित की गई लेकिन इसका विस्तार स्वत: ही सामाजिक, राजनीतिक आदि चिंतन की शाखाओं में धीरे-धीरे हो गया। यह इकाई उदारवाद का उस रूप में वर्णन भी करती है, जैसा कि यह विभिन्न विचारधाराओं में दिखाई देती है। यह उदारवादी राज्य के उद्भव के साथ-साथ असमानता, राज्य की भूमिका आदि विभिन्न मुद्दों का परीक्षण भी करता है जैसा कि इन मुद्दों पर उदारवादियों ने ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही हमने नव-उदारवाद की विचारधारा का आकलन करने का प्रयास भी किया और यह भी जाना की उदारवादी दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। अंत में, उदारवादी सिद्धांतों की समालोचनात्मक-मूल्यांकन भी किया गया।

6.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Cowen, M.P. and R.W. Shenton. 1996. Doctrines of Development. Proutledge; London.

Dean, Mitchell 2001. "Michel Foucault : 'A Man in Danger', in George Ritzer and Barry Smart (eds.) Handbook of Social Theory. Sage Publication : London.

Torfing, J. 1999, New Theories of Discourse. Mass : Blackwell.